

श्री दत्ता मेघे : सर, उसमें करेंगे क्या आप ?

श्री सभापति : अगर आपके पडोसी है, सब जानते हैं, तो क्वैश्चन करने की जरूरत ही नहीं है।

श्री दत्ता मेघे : सर, उनको मालूम है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मालूम है।

श्री कमल नाथ : सर, माननीय सदस्य की यह जानकारी सही है कि मुझे मालूम है,

श्री सभापति : फिर आप आपस में ही तय कर लेना। ...**(व्यवधान)**...

श्री कमल नाथ : सर, यह मेरे पडोसी नहीं है, मैं इनका पडोसी भी हूँ। जहां तक जो आप कह रहे हैं, यह एक हजार एकड़ की बात है, इस पर मुझे खुद इसकी चिंता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए मेरे अपने जिले का भी महत्व जुड़ा हुआ है और जो आसपास के इलाके छिंदवाड़ा से जुड़े हुए है, स्वाभाविक है कि उनको प्राथमिकता मिलेगी ? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : क्या बाकी के क्षेत्र को नहीं मिलेगी ? ... **(व्यवधान)**...

श्री मोती लाल वोरा : सर, यह तो बड़ा पक्षपात है , घोर पक्षपात है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, there is an apprehension in the minds of especially the smaller States that economic zones require large tracks of land. There is also an apprehension that this is an old wine in a new bottle. Can the Minister distinguish between the Special Economic Zones which were established earlier and the existing Special Economic Zones? What is the distinction between the two?

SHRI KAMAL NATH: Sir, previously, as I said, there was a regime, there was a regulatory framework which was not under the law passed by Parliament. Obviously, there were facilities which were there in the past. The point was to give it an element of stability, to bring it under the legal statute so that people would have confidence in it. The Government is apt to change certain facilities, certain incentives and certain regulations from time to time. Now that there is an Act passed by Parliament, all the supervisory systems, which are laid down, are defined in the Act. That is the biggest change which has taken place.

बिहार के किशनगंज जिले में चाय का उत्पादन

*322. **श्री मंगनी लाल मंडल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के किशनगंज जिले में गत कुछ वर्षों से चाय की खेती और उत्पादन प्रारम्भ हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार के किशनगंज एवं अररिया जिलों में उन्नत प्रकार की चाय की पैदावार की जा सकती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चाय उत्पादकों को किसी भी स्तर से अब तक प्रोत्साहन नहीं मिला है तथा उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और सरकार उक्त क्षेत्रों में चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां । चाय बागान किशनगंज जिले के तीन ब्लॉकों अर्थात् किशनगंज, ठाकुरगंज तथा पोठिया में लगाए गए हैं। यद्यपि पहला चाय बागान पोठिया ब्लॉक में 1982 में शुरू किया गया था तथापि अधिकांश मौजूदा बागान 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में ही शुरू हुए थे।

(ख) बिहार के किशनगंज एवं अररिया जिलों में चाय उत्पादन की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था इसके परिणामों के अनुसार केवल किशनगंज जिले को चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया था ।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार/चाय बोर्ड द्वारा किशनगंज जिले के लघु उपजकर्ताओं को नवरोपण तथा गुणवत्ता सुधार के लिए सहायता देने हेतु उपयुक्त कदम उठाए गए हैं । किशनगंज जिले के लगभग 85 उपजकर्ताओं को नव चाय रोपण के लिए 127.56 लाख रुपए की सब्सिडी के रूप में 1.19 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई है। चाय बोर्ड को गुणवत्ता उन्नयन तथा उत्पाद विविधीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान 3.30 लाख रु. की सब्सिडी एक क्रीत पत्ती कारखाना को वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, चाय अनुसंधान एसोसिएशन के विस्तार स्कंध के जरिए उपजकर्ताओं को नए चाय बागानों के रख-रखाव हेतु परामर्शी सेवाएं प्रदान की जा रही है।

Production of tea in Kishanganj District, Bihar

† * 322. SHRI MANGANI LAL MANDAL: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that tea gardening and production has started in Kishanganj district of Bihar in the last few years;

† Original notice of the question was received in Hindi.

[17 August, 2005]

RAJYA SABHA

(b) whether it is also a fact that as per survey better quality of tea can be grown in Kishanganj and Araria district of Bihar;

(c) whether it is also a fact that tea growers have not got any incentive from any level and they have to face adverse conditions; and

(d) if so, the details thereof and the steps Government propose to take to encourage tea production in the said areas?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir. Teagardens have come up in three blocks of Kishanganj District viz: Kishanganj, Thakurgunj and Pothia. Though the first tea garden was opened in 1982 in Pothia block, majority of the existing gardens were opened only in late 1990s.

(b) A survey was carried out to explore the feasibility of growing tea in the Kishanganj and Araria districts of Bihar. As per its findings, only Kishanganj district was found to be suitable for growing tea.

(c) and (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Suitable steps have been taken by Government/Tea Board for assisting the small growers' of Kishanganj District in taking up new planting and quality improvement. Around 85 growers in Kishanganj district have already received subsidy amounting to Rs. 127.56 lakhs for new tea planting. Another 25 growers have received a sum of Rs. 1.19 lakhs as price subsidy under the Price Subsidy Scheme. Under the Quality Upgradation and Product Diversification Scheme of the Tea Board, subsidy amounting to Rs. 3.30 lakhs has been disbursed during 2004-05 to one Bought Leaf Factory. Further, advisory services on maintenance of the young tea plantations are being extended to the tea growers through the extension wing of Tea Research Association.

श्री मंगनी लाल मंडल : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि किशनगंज के तीन प्रखंडों में चाय की खेती हो रही है मेरी जानकारी के अनुसार टी बोर्ड ने जो सर्वेक्षण किया था, उसमें किशनगंज में पांच प्रखंडों को गैर-परंपरागत तरीके से चाय के उत्पादन के लिये उपयुक्त पाया था। यह सिर्फ दो प्रखंडों में नहीं हो रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि चाय उत्पादन को

प्रोत्साहन दिया जा रहा है किन्तु सिर्फ सब्सिडी के बारे में स्थिति का उल्लेख किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि टी बोर्ड ने कितने क्षेत्रफल में इस गैर-परंपरागत तरीके से चाय के उत्पादन के लिए भूमि को उपयुक्त घोषित किया था ? उनमें कितने क्षेत्रफल में चाय कि खेती हो रही है और कितने में अभी और चाय की खेती होनी है ? पांच प्रखंडों की मेरी जानकारी है नंबर दो, सब्सिडी के मामले में सरकार ने कहा कि सब्सिडी दी गई है। मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूँ कि कितने एकड़ भूमि में अभी तक चाय का उत्पादन हो रहा है, चाय का उत्पादन हो रहा है, चाय बागान लगा है और कितने चाय प्रसंकरण संयंत्र लगाए गए हैं ? उसमें कितने की सब्सिडी दी जानी चाहिए थी और कितनी दी गई, कितनी बकाया है ? नंबर तीन।

श्री सभापति : नहीं, नंबर तीन नहीं होगा। आप दो का ही पुछ लीजिए।

श्री कमल नाथ : सर, जानकारी के अनुसार किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में लगभग दस हजार एकड़ चार हेक्टेयर भूमि चाय के उत्पादन में सम्मिलित है और इसमें लगभग हजार टी-ग्रोवर्स हैं। इसमें मे लगभग 165 ग्रोअर्स, जो 701 हेक्टेयर से ऊपर उत्पादन हो रहा है, कई प्रकार की केटेगरी में आते हैं, लगभग 50 छोटे में आते हैं, कुछ बड़े में आते हैं। इससे जो लागत टी बोर्ड ने लगाई है, जैसा मैंने अपने जवाब में कहा, 1990 से ही यहां का उत्पादन शुरू हुआ है और कई योजनाओं के अनुसार जो सब्सिडी देने की बात है, 5 ब्लॉक किशनगंज में है, इनको नान ट्रेडिशनल एरिया डिक्लेअर किया गया है, इनमें से लगभग 325 हेक्टेयर में 127 लाख की सब्सिडी दी गई है। इस प्रकार से पूरी सब्सिडी और जो भी योजना है किशनगंज के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा। बहुत सारी टी बोर्ड की योजनाएं हैं, अगर उनके सुझाव इस विषय में हुए, इस की और बढ़ोतरी के लिए, तो उन पर विचार किया जाएगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कल आप बिहार के बजट के समय बोल रहे थे, उस समय इस मामले को आपने नहीं उठाया, उस समय उठाते।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, बिहार के बजट में हमको हमारी पार्टी ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : सभी माननीय सदस्य बिहार पर खुब बोले, लेकिन आप जैसा बता रहे हो, इतने मुख्य विषय के ऊपर किसि ने चर्चा ही नहीं की, उसकी उपेक्षा की, इसका मतलब क्या है ?

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, आपका ध्यान गया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने इस पर विशेष ध्यान दिया। महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत उत्साही मंत्री हैं और बहुत काबिल हैं, मैं इनसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। इन्होंने इसमें पांच प्रखंडों के बारे में चर्चा की है। टी बोर्ड में बहां की प्लांटर्स एसोसिएशंस का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वंहा प्रतिनिधित्व उसे अभी तक नहीं मिला है। विशेष आमंत्रित के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति को कुछ

अवधि के लिए रखा गया था, फिर उसको हटा दिया गया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातों के बारे में जानकारी चाहूंगा। एक, अभी जो 10 हजार एकड़ में चाय की खेती हो रही है, वह 20 हजार एकड़ तक जा सकती है, उससे ज्यादा जा सकती हैं। भूमि का मामला है। बंगाल में एक विशेष व्यवस्था की गई है भूमि उपलब्ध कराने की। 1995 की बिहार कि जो औद्योगिक नीति घोषित हुई, उसमें भी बिहार में भूमि उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गई है, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी? गैर परम्परागत क्षेत्र में चाय उत्पादन के लिए जितने भूखंड को चिन्हित किया गया है, उस भूखंड को उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करेगी?

दूसरे, टी बोर्ड में स्थायी प्रतिनिधित्व टी प्लांटर्स एसोसिएशंस को देने का सरकार विचार रखती है? इन्हीं दोनों बिन्दुओं पर मैं चाहूंगा कि सरकार उत्तर दे।

श्री सभापति : उत्तर देना चाहें तो दे दीजिए।

श्री कमल नाथ : सर, जहां तक जमीन की बात है, उसमें तो केन्द्र सरकार कुछ कर नहीं सकती, वह तो राज्य सरकार की बात है कि वह जमीन उपलब्ध कराए।

जहां तक टी बोर्ड की सदस्यता की बात है, आज असम में, दक्षिण भारत में बंगाल में बहुत अधिक चाय होती है। सबकी अपनी-अपनी मांग है कि उनका प्रतिनिधित्व हो। मैं देखूंगा कि इसमें क्या हो सकता है ताकि इनको प्रतिनिधित्व ...**(व्यवधान)**...

श्री मंगनी लाल मंडल : राज्य सरकार ने अनुशंसा की थी, नहीं मानी गई। कृपा करके इसको मान लिया जाए।

श्री सभापति : प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं महोदय हमारे सप्लिमेंट्री का उत्तर नहीं आया है।

श्री सभापति : हो गया है उत्तर।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, सरकार से मैंने यह जानना चाहा था कि टी बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ...**(व्यवधान)**...

श्री कमल नाथ : जहां तक उत्पादन का सवाल है, जो क्षेत्र हैं उत्पादन के, जैसे असम हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, जहां बहुत अधिक चाय होती है, वे अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। मैं यह कह रहा

हूँ कि इसमें टी बोर्ड की एक सीमा है।

श्री सभापति : वह सब जानते हैं। सीमा आप जानते हैं, सीमा का उल्लंघन करना वे जानते हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री कमल नाथ : सीमा का किस प्रकार उल्लंघन हो सकता है, माननीय सदस्य अगर इस बारे में मुझे कुछ सुझाव दे दें तो उन पर मैं विचार करूंगा।

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न में 'बी' पार्ट का जो उत्तर दिया है, उसकी तरफ़ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 'बी' पार्ट में पूछा गया था - whether better quality of tea can be grown in Kishanganj and Araria districts of Bihar? लेकिन उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि "As per its findings, only Kishanganj district was found to be suitable for growing tea." प्रश्न किया गया था better quality of tea के बारे में, लेकिन इस संबंध में माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ कि किशनगंज ब्लॉक में जो तीन क्षेत्र पाए गए हैं टी ग्रो करने के लिए, उनकी क्वालिटी कैसी है, बैटर क्वालिटी कि टी है या साधारण क्वालिटी की है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, इसमें तीन ब्लॉक नहीं, पांच ब्लॉक हैं, जो कि ठाकूर गंज, पोठिया, किशनगंज, बहादुरगंज और दिघाल बैंक हैं इस प्रकार ये पांच हैं। जहां तक दूसरा एरिया था, अररिया वाला ...(व्यवधान)...

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा : नहीं, मैं क्वालिटी के बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री कमल नाथ : जी हां, अररिया वाले एरिया में टी की, चाय की संभावना नहीं है। जहां तक चाय की क्वालिटी की बात है तो यह साधारण क्वालिटी की चाय है, ग्रीन लीफ़ टी है और अभी तो यह शुरुआत है क्योंकि केवल 10,000 हैक्टेयर पर उत्पादन हो रहा है और जैसे ही समय गुजरेगा तो किस प्रकार की चाय, जैसा कि मैंने कहा कि 1990 के अंत में ही यहां उत्पादन शुरू हुआ, हालांकि 1982 में इसकी जानकारी थी, किन्तु 1990 के अंत में ही यह सब कार्यवाही शुरू हुई, इसके बाद इस पर जांच की जाएगी और टी बोर्ड जो टेक्निकल सपोर्ट दे सकता है, इसमें अवश्य देगा।

SHRI TARINI KANTA ROY: Sir, the issue is that of better quality of tea, and it is very important not only for Kishan Ganj but for the whole tea-growing areas in the country. We are all aware that our world famous Darjeeling tea is also facing a crisis due to deterioration in its quality. I wish to know from the Minister the steps that have been taken for

improving the quality of this world famous tea.

SHRI KAMAL NATH: Sir, the tea industry has been going through a crisis. As I said in this House before, when there was the boom period of the tea industry, adequate ploughing back of profits and capital for rejuvenation, or, replanting of tea bushes was not done; profits were diverted to other businesses by tea companies. Today, we are faced not only with the quality issues because of the tea bushes being very old, but also with increased production from countries like Vietnam, and with our high cost of production. I have myself had a stakeholders' conference with the entire tea industry, with people representing all segments of the tea industry. A package has been drawn up. Some steps have been taken. A series of steps have been taken. I will be happy to send to the Member details about the steps that have been taken in this regard.

प्रो. राम देव भंडारी : माननीय सभापति जी, चाय के उत्पादन, क्वालिटी और फ़्लेवर की जब चर्चा होती है, उस समय असम, दार्जलिंग, नीलगिरी जैसे क्षेत्रों की चर्चा होती है। मुझे खुशी है कि बिहार के किशनगंज जिले में भी चाय उत्पादन हो रहा है। महोदय, चाय उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किन्तु ऐसा देखा गया है कि बैंको की भूमिका नकारात्मक है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप क्वेश्चन करिए।

प्रो. राम देव भंडारी : मैं क्वेश्चन ही पुछ रहा हूँ, बैंकों के संबंध में।

श्री सभापति : आप तो बता रहे हैं कि बैंकों की कीतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

प्रो. राम देव भंडारी : कोलेट्रल तकनीक देने के बाद भी चाय निर्माताओं और चाय उत्पादकों को ऋण उपलब्ध करवाने के संबंध में बैंको का रवैया सहयोग वाला नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि चाय निर्माताओं एवं उत्पादकों को सुलभ तरीके से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार क्या सुनिश्चित व्यवस्था करना चाहती है।

श्री कमल नाथ : महोदय, हमारी ओर से तो मैं माननीय सदस्य की तरफ़ ही हूँ और हम यह भी चाहते हैं कि चाय उत्पादकों को बैंक की पूरी सहायता मिले। इनकी जो भावनाएं हैं, उनके संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अवश्य सूचित कर दूंगा।

PROF. P.J. KURIAN: Sir, it is good that the Government is taking steps for tea cultivation in Kishan Ganj and other districts of Bihar. But the paradox is that the Government is not able to ensure remunerative price to the existing tea growers. Now, because of the Indo-Sri Lankan

agreement, cheap tea is coming into the country. A number of tea companies are now closed in the country because they were not able to give remunerative price to the tea growers. Therefore, I would like to know from the hon. Minister what steps the Government would take to ensure that remunerative prices are given to the tea growers of Bihar and also of other States.

SHRI KAMAL NATH: Sir, the first part of the supplementary is about Sri Lanka. Sir, sometimes, it is alleged that tea is coming from Sri Lanka. Tea imports from Sri Lanka under the Trade Agreement entered into with Sri Lanka about four years ago are very, very little, and those are not in any way affecting the price. The question is that tea prices are not determined by the Government. The tea prices today are determined globally and with increased production from Vietnam, Kenya and Sri Lanka, obviously, that has impact on tea. In any case, our prices are higher; our labour cost is higher because of the bushes in the tea gardens, our productivity is much lower. So, we are faced with this problem. Whatever can be done under the various schemes of the Tea Board, we are working prices have gone up compared to last year, substantially. There was a decline, and the prices had gone down to Rs. 62. No, they are prevailing at Rs. 70-71. The last month's price was roughly Rs. 71. So, tea prices have started looking up. But, at the end of the day, it is the world prices which drive the tea prices in India, which is very natural.

डा. कुमकुम राय : धन्यवाद महोदय, बिहार के चाय उत्पादकों को जो मुश्किलें आ रही हैं उसमें एक मुश्किल यह है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो वैट लागू हुआ है, उसमें बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिमी बंगाल में चाय पर वैट दर का जो निर्धारण किया गया है वह तो 4 प्रतिशत है, लेकिन बिहार राज्य में चाय पर वैट दर साढ़े बारह प्रतिशत है, इस कारण बिहार के चाय उत्पादकों को बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि चाय पर वैट की जो दर निर्धारित की गई है, उसमें समरूपता लाने के लिए आप कोई प्रयास करेंगे या नहीं ?

श्री कमल नाथ : सर, वित्त मंत्री जी को मैं कहूंगा कि वैट समिति में इस पर आवश्यक चर्चा करें व निर्णय लें।

श्री एस. एस. अहलूवालिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि टी बोर्ड ने समय-समय पर जो सर्वे कराए, खास करके किशन गंज और नौरथ बिहार के कुछ इलाकों के और उसमें उन्होंने यह अनुशंसा की कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और्गनिक टी उत्पादन करने पर जो ट्रेडिशनल टी उत्पादन है उस पर

जो सब्सडी मिलती है या जो सिक टी इण्डस्ट्री है या जो टी प्वाइन्ट है, उनको जो सब्सडी देते हैं, उसमें और और्गेनिक टी प्लांट गोअर्स को कितनी सब्सडी का अंतर रखा है और उसको लागू किया है या नहीं किया है, यह बताने की कृपा करें ?

श्री सभापति : अभी लागू नहीं किया है।

श्री कमल नाथ : सर केवल और्गेनिक टी की बात नहीं है, आज हर चीज और्गेनिक आ रही है और इस पर ध्यान जा रहा है तथा इसका ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसलिए और्गेनिक टी के लिए और और्गेनिक फ़ार्मिंग के लिए भी योजना बनाई जा रही है और और्गेनिक टी को हम प्रमोट करें, यह हमारा प्रयास और इसके बारे में तो भविष्य ही बताएगा, क्योंकि केवल भारत के और्गेनिक टी बना लेने से ही समस्या हल नहीं होगी, बल्कि दूसरे देश भी बनाएंगे, इस पर प्रयास किया जा रहा है।

श्री एस. एस. अहलूवालिया : दूसरे देश बना रहे हैं।

सस्ते चीनी टायरों का घरेलू टायर उद्योग पर प्रभाव

*323. **श्री मती माया सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में नेपाल और अन्य देशों के रास्ते से बड़ी संख्या में चीनी टायर आ रहे हैं तथा उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है जिसके फ़लस्वरूप घरेलू टायर उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और यह गहरे संकट से गुजर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और घरेलू उद्योग को संकट से उभारने तथा चीनी टायरों का देश में अनधिकृत आयात रोकने के लिए अब तक की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी ? नहीं। भारत में बेचे जाने वाले 1 प्रतिशत से भी कम आटोमोटिव टायर चीन के होते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Effect of cheap chinese tyres on domestic tyre industry

† *323 SHRIMATI MAYA SINGH: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large number of Chinese tyres are coming

† Original notice of the question was received in Hindi.